स्वीकृति के लिए लम्बित परियोजनाएं

*133. श्री कैलाश नारायण सारंग : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1992 से 1 नवम्बर, 1992 तक वन संरक्षण अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश की कितनी परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित थी;

(ख) गत दस महीनों के दौरान कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई;

(ग) यदि शेष परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रथम चरण से संबंधित मामलों को, जिनके संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिये गये हैं; स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं और ऐसे मामलों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) 31-10-1992 की स्थिति के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश के 38 प्रस्ताव लम्बित थे।

(ख) 1-1-1992 से मध्य प्रदेश के 50 प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी दी गई है।

(ग) राज्य सरकार के पूर्ण सूचना प्राप्त होने के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को अन्तिम रूप से मंजूर करने के लिए उनकी शीघ्र जांच की जाती है।

(घ) जिन प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में मंजूर कर लिया गया है, उनके संबंध में राज्य सरकारों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत औपचारिक मंजूरी शीघ्र दे दी जाती है।

Setting up of International Commission on Global Environment

*135. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI VISHNU KANT SHASTRI:

Will the MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mr. Shozapura Nakamura, Director-General of Environmental Agency of Japan discussed the seting up of an international commission on sustainable development and restructuring of the global environment with the Indian Government during his recent visit;

(b) if so, what are the salient ponits discussed;

(c) whether Japan has agreed to advance a loan of Rs. 403 crores for the Yamuna River Action Plan; and

(d) if so, what are the details of the project proposed to be covered by the Yamuna Action Plan ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) and (b) Mr. Shozapura Nakamura, Minister of State and Director General of the Environmental Agency of Japan, visited New Delhi on 10-12 September, 1992 and views were exchanged on bilateral matters as well as concerning the structure and mandate of the proposed Commission on Sustainable Development to be set up by the United Nations for the follow-up on the decisions taken at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro (Brazil) during June, 1992.

(c) and (d) Japan has pledged a loan of 17.77 billion Yen (equivalent to Rs. 401 crores) for taking up schemes in 15 towns for the abatement of pollution of the river Yamuna.

राजस्थान में कपड़ा (काटन) मिलों की स्थापना

*136. श्री शिवचरण सिंह क्या वस्त्र मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी मात्रा में कपास की पैदावार होती है ;